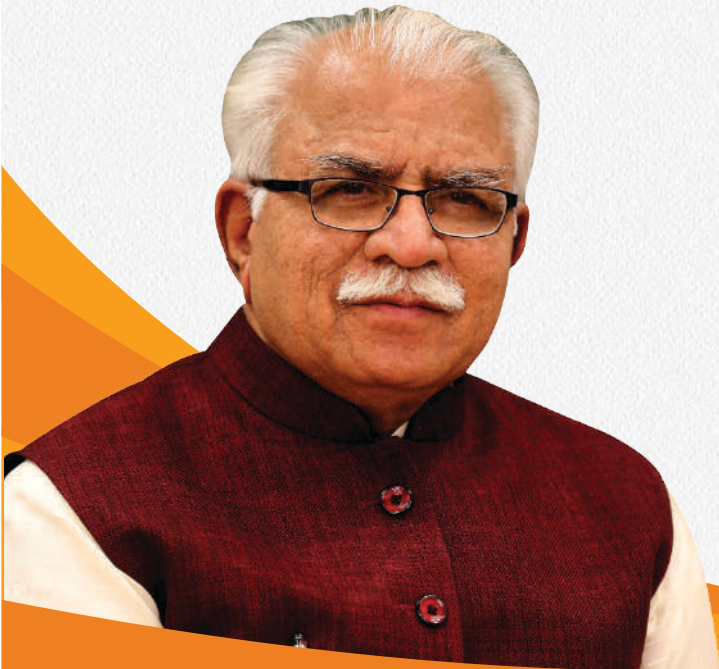


75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 02.01.2023 से 07.01.2023)



भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समारोह

(दिनांक 02.01.2023)



प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्व विद्यालय, माउंट आबू, राजस्थान में 'आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए अनुयायियों तथा प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से

आह्वान किया कि वे सर्वप्रथम गरीबों व वंचितों के उत्थान के लिए कार्य करें ताकि वे लोग मुख्यधारा में आकर समाज निर्माण में भागीदार बन सकें। इस अवसर पर समाज बदलाव का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कविता की पंक्तियां सुनाते हुए कहा कि "चलो जलाएं दीप वहां, जहां अभी भी अंधेरा हो" अर्थात् सबसे पहले अंतिम पायदान



साप्ताहिक सूचना पत्र

पर खड़े व्यक्ति के घर उजियारा कर उसके जीवन से दुख, दर्द व दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इस मौके पर दादी प्रकाशमणी पार्क के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समय-समय पर समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और उन्होंने समाज सुधार के लिए कार्य किए। अलग-अलग भाषाओं में महापुरुषों की शिक्षाएं रही हैं, परंतु सभी संतों का मूलभाव यही है कि किस प्रकार समाज में सुधार लाया जाए।

ऐसे सभी संतो-महापुरुषों की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने संत-महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई है, जिसके तहत सभी महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ब्रह्मकुमारीज संगठन का लक्ष्य भी समाज सुधार के



साथ-साथ मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करना है। सरकारें विकास कार्य करती हैं, जिसे भौतिक विकास की संज्ञा दी जाती है, लेकिन सरकारों का काम केवल भौतिक विकास ही नहीं बल्कि समाज में आध्यात्मिक विकास करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना, जिनमें शिक्षा, संस्कार के साथ ही उनका मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास भी हो, यही सरकार तथा सामाजिक संगठनों का ध्येय होना चाहिए।



साप्ताहिक सूचना पत्र

भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही

(दिनांक 02.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम में आज हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने वर्ष 2023 के पहले मामले में जबरन वसूली, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप में 2016 बैच के एक एचसीएस अधिकारी व उसके परिवार के तीन सदस्य एक चाचा और दो भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

वर्तमान में एचसीएस अधिकारी हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के सदस्य सचिव के पद पर तैनात है। एचसीएस अधिकारी और उसके भाई को हाल ही में हुए नूंह जिला परिषद चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के बहाने एक महिला उम्मीदवार से 9,60,000 रुपये की मांग और स्वीकृति के आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में आने वाले सबूतों के बाद गिरफ्तार किया गया है। सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते

हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एचसीएस अधिकारी वकील अहमद और उनके भाई फखरुद्दीन के रूप में हुई है।

इसके साथ ही हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने नूंह में तैनात जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को स्कूल डेस्क की सप्लाई करने के खरीद आदेश शिकायतकर्ता के पक्ष में करने की एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अधिकारी की पहचान रामफल धनखड़ के रूप में हुई है, जो शिकायतकर्ता के पक्ष में स्कूल डेस्क की सप्लाई के लिए खरीद आदेश सुनिश्चित करने के एवज में 10 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था। ये डेस्क नूंह जिले के विभिन्न स्कूलों में सप्लाई किए जाने थे। आरोपी अधिकारी पहले भी 2 लाख रुपए रिश्वत ले चुका है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

किसानों के लिए स्थापित हो रहे उत्कृष्टता केंद्र

(दिनांक 03.01.2023)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्षों से प्रदेश सरकार किसान व किसानों के प्रति गंभीर है और केंद्र सरकार की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हर योजना को अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पहले मुर्तरूप दे रही है।

इसी के चलते प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में गुणवत्ता व उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए 11 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। इन उत्कृष्टता केंद्रों से अनेकों किसानों को जोड़ा गया है इसके अलावा, 'विलेज ऑफ एक्सीलेंस' के माध्यम से भी बेहतर कृषि, बागवानी व पशुपालन में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज करने वाले गावों को चिन्हित किया गया है।

किसान उत्पादक समूह सीधे बाजार से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत बागवानी फसलों का 40 हजार रुपए प्रति एकड़ बीमा किया

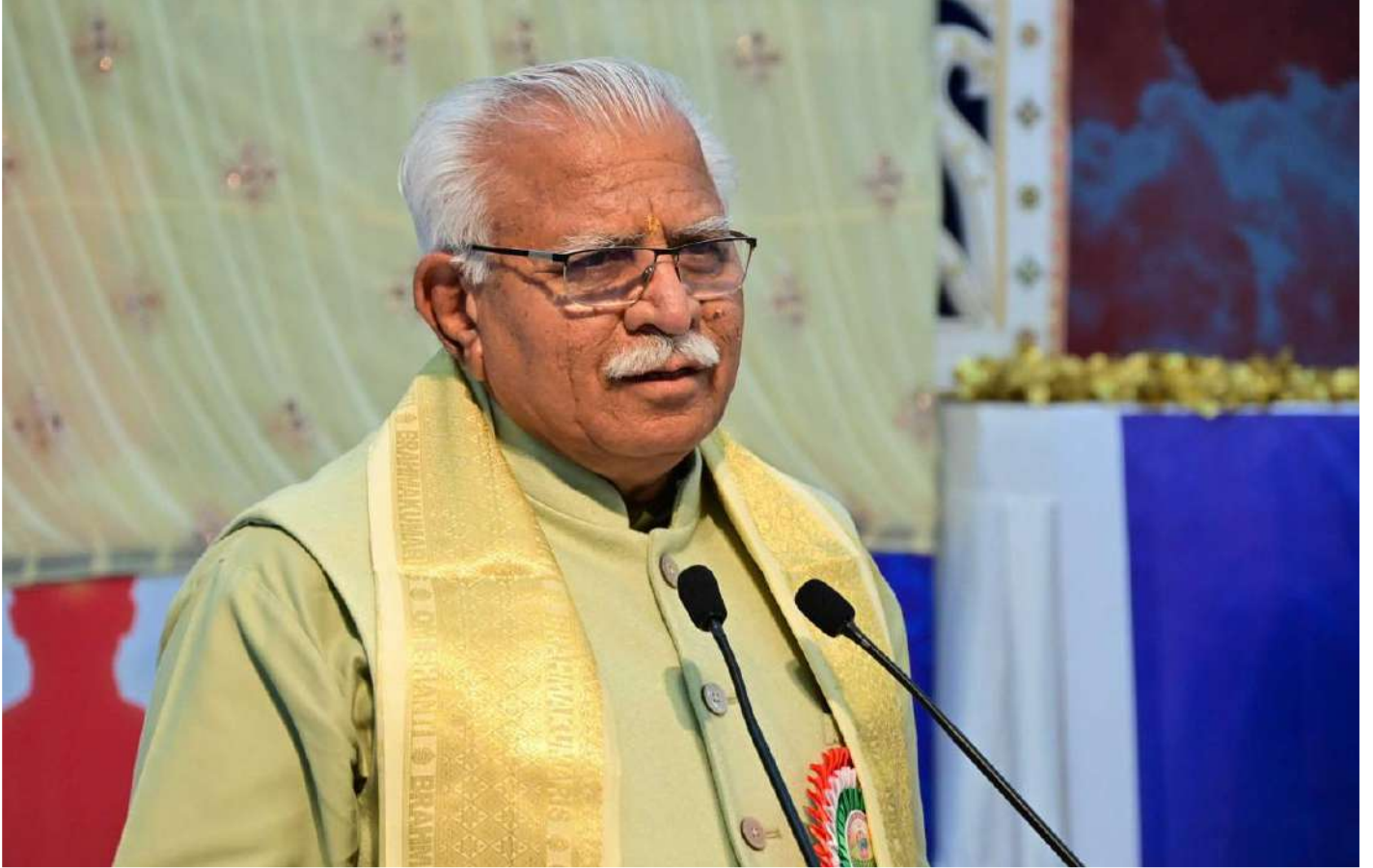
जाता है। राज्य में बागवानी का क्षेत्र पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। राज्य के किसानों का रुझान परंपरागत खेती की जगह बागवानी की ओर हो रहा है।

किसानों का रुझान पारंपरिक खेती के साथ-साथ अन्य नकदी फसलों की ओर बढ़े, इसके लिए न केवल केंद्र सरकार क बल्कि दूसरे देशों के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र खोल रही है, जिसके तहत किसानों को बागवानी व मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई-नई तकनीकों की जानकारी दी जाती है और किसान इन्हें अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने एक अनूठी पहल करते हुए मेरा पानी, मेरी विरासत नाम से एक नई योजना आरंभ की, जिसके तहत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ वित्तीय



साप्ताहिक सूचना पत्र



सहायता दी जाती है।

इसके अलावा डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा किसानों को दिया जा रहा है। प्रदेश का किसान आज नई तकनीक का उपयोग कर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहा है। हरियाणा के दो प्रगतिशील किसानों को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है।

इन दोनों किसानों को परम्परागत खेती से हटकर स्वीट कॉर्न व बेबी कॉर्न तथा मत्स्य पालन में उत्कृष्टता के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री जी ने एक और अनूठी पहल करते हुए जो प्रगतिशील किसान कम से कम 10 और किसानों को प्रगतिशील किसान बनने के लिए प्रेरित करेगा उसे किसान श्री पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

ग्रुप-डी पदों पर भर्ती के लिए जल्द होगी सीईटी परीक्षा

(दिनांक 03.01.2023)

प्रभाव : आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की की हरियाणा में ग्रुप-डी पदों की भर्ती के लिए जल्द ही कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी प्रशासनिक सचिवों को 7 जनवरी, 2023 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) को अपने विभागों के ग्रुप-डी पदों की नई व लंबित मांग भेजने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव जी ने बताया कि ग्रुप-डी

के कुछ पदों जैसे कुक, नाई, वेटर, ड्रेसर, क्लीनर, एनिमल अटेंडेंट, मोची, माली, बढई, पेंटर, दर्जी आदि में विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसलिए, इन श्रेणियों को विशेष अनुभव और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि एचएसएससी को मांग पत्र भेजने के दौरान अपने विभाग में ग्रुप-डी के उन विशेष पदों के बारे में उल्लेख करें जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

SYL का मुद्दा

(दिनांक 05.01.2023)

प्रभाव : SYL को लेकर दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी के साथ पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि एसवाईएल बनेगी और इसके निर्माण के लिए दोनों राज्य आपसी सहमति पर आएंगे। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री और अधिकारी एसवाईएल कैसे बने, इस एजेंडे पर आना ही नहीं चाहते।

वो हमेशा पानी के बंटवारे की बात करते हैं। जबकि पानी के बंटवारे के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, यदि पानी के बंटवारे को लेकर कोई बात कहनी है, तो ट्रिब्यूनल के सामने सारी बात रख सकते हैं, जो भी बंटवारा होगा, उस हिसाब से पानी मिलेगा। लेकिन उसके लिए एसवाईएल का बनना जरूरी है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसवाईएल के समाधान

के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के पास कोई फॉर्मूला है, तो वे पंजाब के मुख्यमंत्री को बता दें और जब हमारी बैठक होती है तो पंजाब के मुख्यमंत्री सबके सामने उस फॉर्मूला को सुझाएं।

यदि फिर भी वे कोई फॉर्मूला बताना चाहते हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट को बताएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पानी के पानी की जरूरतों को पूरा करना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है। हरियाणा दिल्ली को जितना पानी दे रहा है, उसमें से अधिकांश हिस्सा पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली को उसका पूरा पानी दे रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली के पानी को कम करने का कोई कारण नहीं बनता है, हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। हालांकि, हरियाणा में पीने के पानी के साथ-साथ एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए भी उपयोग में लाया जाता है।



साप्ताहिक सूचना पत्र



साप्ताहिक सूचना पत्र

गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एनिमेशन एवं मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन

(दिनांक 05.01.2023)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में एनिमेशन एवं मल्टीमीडिया लैब का आज उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव कांकरौला के सेक्टर -87 में 44 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे विश्वविद्यालय के टीचिंग ब्लॉक का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोजगार की असीम

संभावनाओं एवं समय की मांग को देखते हुए गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी (एनिमेशन) कोर्स की शुरुआत करना एक सराहनीय पहल है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एनीमेशन एवं मल्टीमीडिया की प्रायोगिक शिक्षा मिल सके, इसी उद्देश्य से अत्याधुनिक कम्प्यूटिंग लैब विकसित की है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को एनिमेशन फिल्म मेकिंग में 3डी एनिमेटिड डिजिटल ऑब्जेक्ट बनाना सीखने तथा स्पेशल इफेक्ट्स इत्यादि का अभ्यास मिल सकेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा तीन वर्षीय बीएससी एनिमेशन व मल्टी मीडिया का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। पाठ्यक्रम में औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप विद्यार्थियों को हर प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।



साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा वक्फ बोर्ड सम्मान समारोह

(दिनांक 05.01.2023)



प्रभाव : मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम में हरियाणा वक्फ बोर्ड के ईमामों के साथ बैठक की और उनसे आह्वान किया कि सभी इक्कट्टे रहकर समाज में काम करें तो देश उन्नति की राह पर तेजी से अग्रसर होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज व आवाम सबका भला होना चाहिए। सबको एकता के सूत्र में पिरोना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जबसे देश की बागडोर संभाली है,

उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कई तरमिमें की हैं। तीन तलाक पर बनाए गए कानून को आम जनमानस ने अच्छा माना है। ऐसे तथ्यों के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सफल बनाने में मौलाना व ईमामों ने सराहनीय योगदान दिया है। इसी प्रकार समाज में फैल रही नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर करते हुए ईमामों से अपील



साप्ताहिक सूचना पत्र

की कि वे नशाखोरी को रोकने में अपना योगदान दें। ईमामो के साथ बातचीत में शिक्षा का विषय रखा और कहा कि चाहे स्कूल हो या मदरसे, हमें शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहिए, इसलिए अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाएं। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मेवातवासी उद्योग लगाने या यहां उद्योग लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित करने के लिए आगे आएंगे। मुख्यमंत्री जी

ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में प्रदेश के हर परिवार का विवरण दर्ज है और इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है।

अब पात्रता होने पर ऑटोमेटिक वृद्धावस्था सम्मान पेंशन बनेगी और बीपीएल का राशन कार्ड बनेगा, ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है। ईमामों को अभूतपूर्व सौगात देने के लिए 'तंजीम आईमा-ए-ऑकाफ' हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था।



साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

(दिनांक 06.01.2023)

प्रभाव : हरियाणा एक— हरियाणवी एक के मूलमंत्र पर चलते हुए प्रदेश का समुचित विकास करने की प्रतिबद्धता को पुनरु दोहराते हुए मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम के गांव धनवापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, विद्युत, सड़क नेटवर्क सुदृढीकरण इत्यादि से संबंधित 791 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 113 परियोजनाओं का

उद्घाटन तथा 1090 करोड़ रुपये की लागत की 54 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास की गई 12 प्रमुख परियोजनाओं में पृथला, पलवल एवं हथीन विधानसभा क्षेत्रों के 84 गांवों के लिए रैनीवैल आधारित पेयजल वृद्धि परियोजना, सतनाली खण्ड के 25 गांवों में नहरी जल पर आधारित पेयजल आपूर्ति के लिए नए जल संशोधन



साप्ताहिक सूचना पत्र



संयंत्र, दिल्ली हिसार रोड, शीला चौक पर ऊपरगामी पुल, रोहतक खरखौदा दिल्ली बॉर्डर रोड पर जेएलएन फीडर और बी एस बी नहर पर स्टील के पुल के कार्य का उद्घाटन तथा भिवानी-हांसी मार्ग का तोशाम बाई दृपास से जोड़ने वाले रेलवे ऊपरगामी पुल का उद्घाटन शामिल है।

गुरुग्राम के धनवापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिलों को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वित्तमंत्री के रूप में हमने अपने बजट का नियोजन

सही किया है और आज हमारे बजट का 34.5 प्रतिशत हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है।

उन्होंने कहा कि हर विभाग का एक निश्चित बजट होता है, हालांकि कभी-कभी वित्त वर्ष के अंत में कुछ विभागों का बजट बच भी जाता है और विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के बजट की कमी ना आये इसके लिए हमने एक नई पहल करते हुए मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर रिज़र्व फण्ड बनाया है।

इसी प्रकार एक और नई पहल करते हुए गांवों और शहरों में भी विकास कार्यों में तेजी लाने हेतु ग्राम दर्शन एवं नगर दर्शन पोर्टल शुरू किया है जिन पर नागरिक अपने इलाके की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों की मांग पोर्टल पर कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर काम कर रही है और इस वर्ष ग्रुप सी की 35 हजार और ग्रुप डी



साप्ताहिक सूचना पत्र

की 15 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार भी बड़े स्तर पर भर्तियां करने जा रही है जिसका लाभ हरियाणा के युवाओं को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि गरीब का हक पहले हो इसलिए अंत्योदय की भावना से काम करते हुए हम आगे बढ़े हैं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम जिला के गांव धनवापुर में 50 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और स्वयं उपचारित पानी का बीओडी लेवल चौक किया, जोकि 3 पाया गया। उन्होंने कहा कि जल संसाधन की दिशा में उपचारित पानी का पुनः उपयोग एक महत्वपूर्ण कदम है।

विशेषज्ञों के मतानुसार टरशरी ट्रीटमेंट के बाद यदि सीवरेज के पानी का बीओडी लेवल 10 से कम आता है तो उस शोधित पानी को सिंचाई के लिए तथा उद्योगों में प्रयोग किया जा सकता

है। गुरुग्राम जिला के मानेसर में 25 एमएलडी क्षमता का एसटीपी मानेसर, नाहरपुर, कासन तथा आसपास के गांवों के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है जो अगले एक साल में बनकर तैयार होगा। यही नहीं, गांव धनवापुर में भी एक और 100 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा जिसकी आधारशिला आज रखी गई है। इस प्लांट के सितंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है। ये सभी सयंत्र पूरी तरह से टरशरी ट्रीटमेंट की सुविधा से युक्त होंगे।



साप्ताहिक सूचना पत्र

जीएमडीए की 11वीं बैठक

(दिनांक 06.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की 11वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में गुरुग्राम शहर के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। अथॉरिटी का वार्षिक बजट भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा

होगा। बैठक में केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता और परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद थे। बैठक में जीएमडीए की 10वीं बैठक की कार्यवाही को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में निम्नलिखित परियोजनाओं को



साप्ताहिक सूचना पत्र

स्वीकृति दि गई। बहरामपुर एसटीपी से नूह डिस्ट्रीब्यूटरी तक पाईप लाईन बिछाकर सीवरेज के शोधित जल को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

लगभग 618 करोड़ रुपये के इस प्रस्ताव को प्राधिकरण की बैठक में मंजूर किया गया। नजफगढ़ ड्रेन के साथ लगती जलमग्न रहने वाली लगभग ढाई हजार एकड़ कृषि भूमि को बचाने के उपायों पर भी चर्चा हुई।

लगभग 97 एकड़ में एक झील बनाकर किसानों की जमीन को जलमग्न होने से बचाया जाएगा। लैग-2 और 3 को नजफगढ़ ड्रेन के साथ जोड़ा जाएगा। वर्तमान में यहां पर गुरुग्राम शहर के सीवरेज का पानी जा रहा है जिसे रोकने के लिए एसटीपी बहरामपुर से नूह डिस्ट्रीब्यूटरी तक पाईप लाईन बिछाने को मंजूरी दी गई है।

चंदू बुढेड़ा जलघर में रैस्को मोड पर सोलर पॉवर प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

लगभग 4 मेगावॉट क्षमता का यह प्लांट लगेगा जिससे जलघर को सस्ती बिजली मिलेगी और पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा।

बैठक में लगभग 18 एकड़ में वजीराबाद झील के विकास के लिए जीएमडीए के शहरी पर्यावरण प्रभाग द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें वॉकिंग ट्रैक के निर्माण के साथ-साथ सीवरेज के पानी की निकासी, डीसिल्टिंग, झील को उपचारित पानी उपलब्ध कराना और इसकी सीमा के साथ फेंसिंग लगाना शामिल है।

गुरुग्राम के नागरिकों के लिए झील क्षेत्र को अवकाश स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सीएसआर के तहत विभिन्न पहलें भी की जा रही हैं।

बैठक में जीएमडीए का नया अपना कार्यालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। जीएमडीए सेक्टर-16 में जलघर के साथ में लगभग 2 एकड़ भूमि पर अपना नया कार्यालय बनाएगा।



साप्ताहिक सूचना पत्र

मुख्यमंत्री जी ने चिरायु योजना के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद

(दिनांक 07.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता मेरा परिवार है, जिसके हित में जनकल्याण के लिए पिछले 8 वर्षों में कई बदलाव किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि समाज की अंतिम पक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना हमारी सरकार दायित्व है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिले। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति को घर बैठे राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन आदि जनकल्याण की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में जो समस्याएं आ रही हैं उनको धीरे-धीरे ठीक किया जा रहा है। सरकार गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए 'सर्वजन हिताय—सर्वजन सुखाय' को चरितार्थ करना है। हम पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ जनकल्याण से जुड़ी सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने की मुहिम में और अधिक तीव्रता लाएंगे।

'अंत्योदय' के आदर्श पर चलते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश में उन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि समाज में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए ओर समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करें।

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना उनके लिए



साप्ताहिक सूचना पत्र

वरदान साबित हो रही है। महंगी बिमारियों के ईलाज के खर्च के कारण अब इन परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले उन परिवारों को बी.पी.एल में शामिल किया गया था जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से कम थी। राज्य सरकार ने यह आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस वर्ष के दौरान हमारा यही प्रयास है कि हर व्यक्ति निरोगी रहे और बिमार न हो। परंतु फिर भी यदि बिमारी रूपी संकट गरीब परिवारों पर आता है तो वे आयुष्मान भारत तथा चिरायु हरियाणा योजना का लाभ उठाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिरायु योजना शुरू करने से पहले आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 28,89,287 व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए गए थे। चिरायु योजना के तहत अब 44,15,771 और व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं।



इन्हें मिलाकर गोल्डन कार्ड पाने वालों की संख्या बढ़कर 73 लाख से अधिक हो गई है। इस माह के अंत तक सब लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बना दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेज गति और पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है।

